ISSN 0975-119X

.UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 1 जनवरी-फरवरी 2020

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

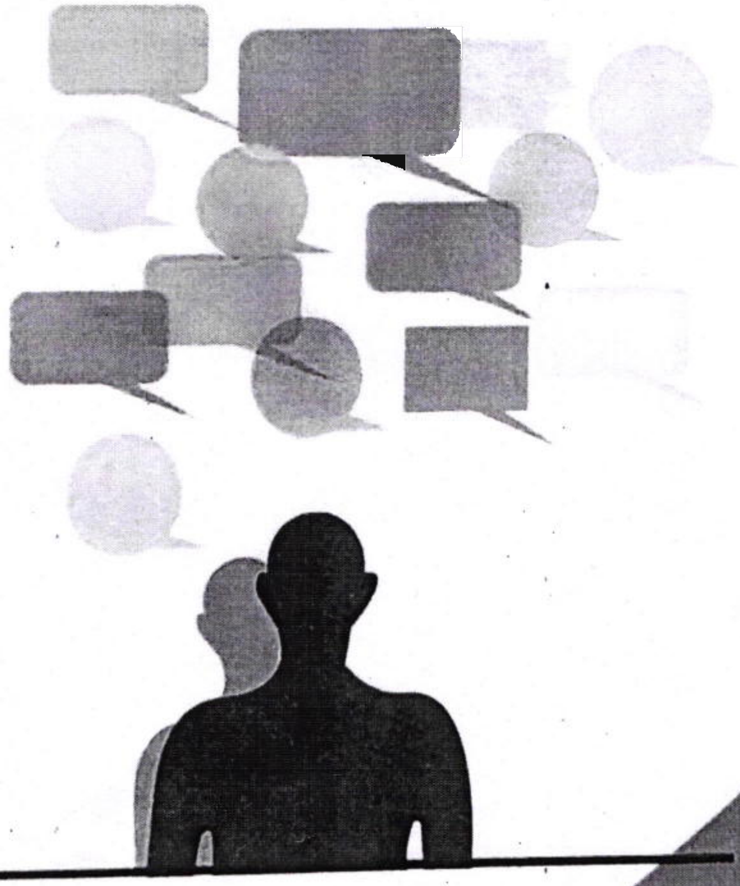

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

R.C.S. Arts & Commerce College
DURG
Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

स्नातक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन रवि; डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह 559
माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र के आधार पर शिक्षकों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन-शारदा प्रसाद सिंह; डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह 563
उत्तर भारत की जनजातियों में जल, जंगल एवं जमीन की समस्याएं एवं समाधान-अवन्तिका 567
आंचलिक उपन्यास: स्वरूप और उपकरण-डॉ० शिवम 571
अकादमिक पुस्तकालय सेवाएं एवं ई० संसाधन अनुप्रयोग: उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक अध्ययन-पूजा संजय भारती, पूनम वर्मा 574
भारतीय पत्रकारिता पर औपनिवेशिक संस्कृति का प्रभाव-मुन्ना लाल पाल 578
डॉ० जयप्रकाश कर्दम की कहानियों में नारी जीवन-श्रीमती पंकज यादव 581
पशु कल्याण: चुनौतियां एवं समाधान-डॉ० शैलेन्द्र सिंह 584
दलित जीवन को उजागर करती आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन-डॉ० ज्योति सिन्हा 588
भारत की आर्थिक समीक्षा में मानव विकास का अध्ययन-इन्दु आर्या 592
मध्यकालीन समाज में स्त्री और मीराबाई-डॉ० दीप कुमार मिश्रा 596
भारत में महिला प्राथमिक शिक्षा की स्थिति-गणेश कुमार 599
शिक्षा सम्बन्धित अधिनियम एवं उच्च शिक्षा की महिला अध्येताओं की जागरूकता-वन्दना शर्मा; डॉ० वन्दना गोस्वामी; डॉ० अजय शुक्ला 604
समकालीन हिन्दी कविता की प्रकृति-डॉ० श्रीनिवास सिंह यादव 608
भारत में महिलाओं की स्थिति और विकास का एक अध्ययन-डॉ० अनिल झा 613
आधुनिक भारतीय राजनीति में वंशवाद-दीपक कुमार राय 616
शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक मूल्यों का अध्ययन-डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय 619
चन्द्रकिरण सौनरेक्सा के कहानी संग्रह 'आधा कमरा' की समीक्षा: एक दृष्टि-विनोद कुमार सिंह 623
ध्यान: उपनिषदों के आलोक में-नम्रता चौहान; डॉ० श्याम गणपत तिखे 626
स्वावलंबन: एक यौगिक दृष्टि-अखिलेश कुमार विश्वकर्मा; डॉ० श्याम गणपत तिखे; डॉ० उपेन्द्र बाबू खत्री 631
जैन दर्शन में ध्यान का स्वरूप-धनंजय कुमार जैन; डॉ० उपेन्द्र बाबू खत्री 636
भारत में पर्यावरण और जलवायु से जुड़े खतरे-डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 640
संस्कृत भाषा की उत्पत्ति एवं प्रवृत्ति एवं पाणिनि का योगदान-डॉ० योगिता मकवाना 642
शहरीकरण के प्रभाव और प्रबंधन-रामावतार आर्य 645
सामाजिक मानव मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में आज की हिन्दी कविता-प्रद्योत कुमार सिंह 648
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था-समस्या और समाधान-डॉ० आयशा अहमद 653
पंचायती राज व्यवस्था व महिला नेतृत्व-डॉ० राम नरेश टण्डन 656
वर्तमान में नक्सलवाद: समस्या एवं समाधान-डॉ० भूपेन्द्र कुमार 659
ग्राम स्वराज एवं ग्रामीण विकास पर महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता-डॉ० विजय कुमार साहू 663
आयुर्वेद के अनुसार रजःस्वलाकाल में आहार: एक अध्ययन-नेहा सैनी; डॉ० तिखे श्याम गणपत 666
पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज और गोरखनाथ-डॉ० सर्वेश चन्द्र शुक्ल 670
पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण की अवधारणा-डॉ० प्रमोद यादव; आशीष नाथ सिंह 672
"छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के संबंधों का एक व्यवहारिक अध्ययन" (राज्य मंत्रालय के विशेष संदर्भ में)
-डॉ० (श्रीमती) अलका मेश्राम; डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; दीपा 677
औद्योगीकरण का ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव-डॉ० जवाहर लाल तिवारी; दिनेश कुमार 681
रायपुर जिले के विकास में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की भूमिका का एक राजनीतिक विश्लेषण
-डॉ० (श्रीमती) रीना मजूमदार; डॉ० प्रमोद यादव; फैसल कुरैशी 686
ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका-डॉ० प्रमोद यादव; कमल नारायण 690
महिला आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का एक राजनीतिक विश्लेषण
(रायपुर जिले के ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में)-डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; स्वयंप्रभा भूतलहरे 694
आर्थिक एवं सामाजिक विकास में आने वाली समस्याओं के कारण एवं निवारण में जिला प्रशासन की भूमिका
-डॉ० (श्रीमती) अलका मेश्राम; डॉ० डी० एन० सूर्यवंशी; रामकृष्ण साहू 698

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका

डॉ० प्रमोद यादव

(निर्देशक) सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), एस. आर. सी. एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

कमल नारायण

शोधार्थी, एस.आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया। उनकी यह धारणा थी कि भारत गांव का देश है, जब तक ग्रामीण विकास समाज और नगरी समाज के विकास कार्यक्रमों में संतुलन नहीं होता है, तब तक संपूर्ण भारत का आर्थिक सामाजिक रूप से विकास होना संभव नहीं है गांधी जी की यह धारणा थी कि भारत गांव का देश है इसकी उन्नति तभी संभव है इसकी उन्नति तभी संभव है जब हम गांव को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाये।

नेहरू जी की यह धारणा थी, कि समाजवादी कार्यक्रमों के द्वारा ही भारत के करोड़ों दीन हीन गरीबों और पिछड़े व्यक्तियों का कल्याण किया जा सकता है उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाया जा सकता है। इस दृष्टि से देश के संपूर्ण आर्थिक ढांचे को बदलने की आवश्यकता है अंग्रेजों के आर्थिक मॉडल के आधार पर ग्रामीण समाज की उन्नति संभव नहीं है यह संभव नहीं है इसलिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है।

भारत एक अल्पविकसित परन्तु विकासशील राष्ट्र इसका औद्योगिक स्वरूप उन्नत देशों की अपेक्षा भिन्न है, और इस कारण यहां अत्यधिक गरीबी है बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यहां बेरोजगारी दूर करना आवश्यक है। इसके लिए पूंजी वस्तुओं का स्टॉक बढ़ाना आवश्यक है इससे उत्पादन की नई प्रक्रिया कायम होती है बाजार में उत्पादित वस्तुओं की मांग और पूर्ति बढ़ती है। सरकार इस सारी प्रक्रिया को नियोजन के माध्यम से नियंत्रित करती है आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया सन 1952 में प्रारंभ हुई।

जिसमें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर विकास का मॉडल श्रेष्ठ योजना तैयार किया गया है। इन योजनाओं के द्वारा आर्थिक क्रियाओं का इस प्रकार नियोजन किया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास की नीति और कार्यक्रम इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं। बजट का 50% ग्रामीण समाज के विकास पर व्यय किया जाए इस बजट का उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना बेरोजगारी की समस्या का समाधान कृषि सहायक क्रियाओं का विकास करना और ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाना है।

मूल शब्द - विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रशासन तंत्र एवं नेतृत्व

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु एवं सक्षम तथा ईमानदार नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सक्षम सक्षम प्रशासन तंत्र का महत्व इस अर्थ में और भी अधिक हो जाता है, कि इसके द्वारा ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन होता है योजनाओं निर्माण में भी यह प्रशासन तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत में ग्रामीण विकास के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर निम्न प्रकार से की जा सकती है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का नीति सिद्धांत संचालन एवं रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विभाग की स्थापना की गई है यह विभाग ग्रामीण विकास विभाग के रूप में विद्यमान है। ग्रामीण विकास विभाग में प्रमुख सचिव नियुक्त किया जाता है जो इस विभाग का प्रशासनिक नेतृत्व करता है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभागीय स्तर से विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और इसमें महत्वपूर्ण रोजगार, ग्रामीण शिक्षा एवं ग्रामीण विकास आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं।

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

किसी भी शोधकर्ता के लिए यह जरूरी है कि वह पूर्व में किये गए शोध कार्यों का पुनरावलोकन करे, इससे शोध कार्य में [illegible] सहायता मिलती है। इस प्रकार सबसे निचले स्तर की पंचायती व्यवस्था है जहां ग्रामीण लोग ही विकास करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर में नेतृत्व करना जनजाति वर्ग के लिए एक समस्या रहती है जिसका समाधान भी आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में शोध कार्य करने की प्रासंगिकता बनी हुई है।

1) [illegible] (2007) ने ग्रामीण नेतृत्व का बदलता हुआ स्वरूप एक समाजशास्त्रीय अध्ययन में स्पष्ट किया है कि ग्रामों का विकास वहां के रहने वाले युवा विचारों के बगैर नहीं हो सकता। ग्रामों के विकास के लिए सभी ग्रामीण जनता की सहभागिता आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग शिक्षित हो रहे हैं, इसलिए ग्रामीण नेतृत्व में बदलाव देखा जा रहा है। लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और जागरूकता का परिचय देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं।

2) [illegible] (2002) ने भारत में आदिवासी विकास की समस्या को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में आदिवासी निवास करते हैं, जहाँ उनकी विभिन्न समस्याएँ हैं। इन समस्याओं के कारण आदिवासी विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। नेतृत्व करके समस्या का समाधान करने के लिए आदिवासियों में जागरूकता की आवश्यकता है।

3) [illegible] (2002) ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि ब्रिटिशकाल के समय जनजातियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है व अधिक कर्ज में डूबे रहे थे। परिवार के भरण-पोषण के लिये जनजाति साहूकारों एवं जमींदारों से कर्ज लेते थे। आर्थिक समस्या इनके साथ सदैव से रहा था। इस प्रकार जनजातियों के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक शोषण को स्पष्ट किया है।

4) [illegible] विजयशंकर (1999) ने भारत की जनजाति संस्कृति में स्पष्ट किया है कि भारत में अनेक जनजातियां निवास करती हैं जिनकी सांस्कृतिक विशेषताएं विविध प्रकार की हैं इन सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण जनजातियों की अलग पहचान है। जनजाति नेतृत्व में सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश करते हैं। जनजातियों के रीति-रिवाज की भी अलग पहचान है।

5) सिंह राजेन्द्र कुमार (1996) ग्रामीण अभिजन विषय पर पूर्वी उत्तरप्रदेश के विशेष संदर्भ में एक सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के व्यावहारिक पक्ष को इसमें उजागर करते हुये ग्रामीण राजनीतिक परिवेश को स्पष्ट किया गया है, जिसमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान शोध का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन, धमतरी जिले के संदर्भ में किया गया, जिसका उद्देश्य निम्न है।

1. ग्रामीण जनता की समस्याओं के समाधान में जिला प्रशासन की भूमिका का अध्ययन किया गया है।
2. ग्रामीण विकास में जिला प्रशासन की भूमिका पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

शोध की परिकल्पना

शोध की एक पूर्व कल्पना होती है और उसी के माध्यम से एक शोधकर्ता आगे कार्य करता है मेरे द्वारा चयनित इस शोध रूपरेखा में मेरी उपकल्पना है जिला प्रशासन धमतरी द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों तथा विकास में उसकी भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन कर प्रशासनिक व्यवस्था के बेहतर निष्पादन हेतु क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं। शोध की रूपरेखा के अंतर्गत परिकल्पना को सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकार है:-

1. ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के बीच समन्वय का अभाव नहीं है।
2. योजनाओं के हितग्राहियों को वांछित लाभ की स्थिति संतोषप्रद है।

जिला प्रशासन की भूमिका

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विकेंद्रीकृत लोक अनुमति संवेदनशील एवं जवाबदेही प्रशासनिक व्यवस्था निर्मित करने की दृष्टि से जिला प्रशासन की व्यवस्था स्थापित की गई है। ताकि जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही शीघ्रता से निराकरण हो सके इसके लिए जिला योजना समिति को जिला प्रशासन का संस्थागत आधार बनाया गया है। योजना समिति के अधिकांश सदस्य जिला पंचायतों एवं नगर पंचायतों के निकायों द्वारा चुने जाते हैं एवं सांसद विधायक क्षेत्र से आमंत्रित सदस्य होते हैं।

जिला प्रशासन के विभाग अध्यक्ष अधिकार अध्यक्ष अधिकारी इन समितियों को संचालित करते हैं। जिसमें स्थानीय समस्या का समाधान स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं किया जा सके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, कि स्थानीय स्तर में जो अधिकार दिए गए हैं वह यथावत रहे जिला प्रशासन के प्रमुख जिलाधीश जिला समिति का सदस्य एवं सचिव होता है जिन के सहयोग से सभी शासकीय अधिकारी कार्य प्रक्रिया में नियमानुसार निर्णय लेने हेतु समिति की सहायता करते हैं एवं लिए गए निर्णय का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हैं।

Seth R.C.S. Arts & Commerce College
DURG
Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

प्रश्न 01 क्या आप इस बात में सहमत है कि राजनीतिक जन प्रतिनिधि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जिला प्रशासन पर दबाव डालते है।

सारणी क्रमांक 01

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	78	52
2	नहीं	54	36
3	कह नहीं सकते	18	12
	योग	150	100

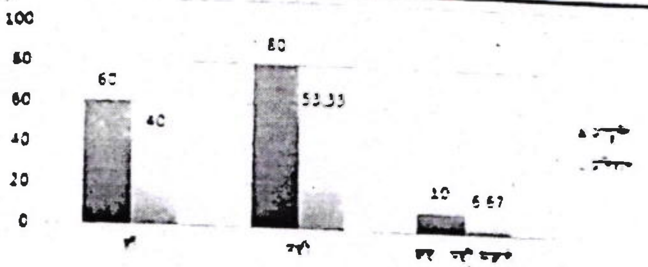

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अध्ययनगत उत्तरदाताओं में से 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि राजनीतिक जन प्रतिनिधि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जिला प्रशासन पर दबाव डालते है। वहीं 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि राजनीतिक जन प्रतिनिधि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जिला प्रशासन पर दबाव डालते है। जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तटस्थता बनाते हुए अपना मत व्यक्त नहीं किया।

प्रश्न 02 क्या जिला प्रशासन को प्रदेश के विरोधी दल के जन प्रतिनिधियों द्वारा आरोपित किया जाता है।

सारणी क्रमांक 02

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	60	40
2	नहीं	80	53.33
3	कह नहीं सकते	10	6.67
	योग	150	100

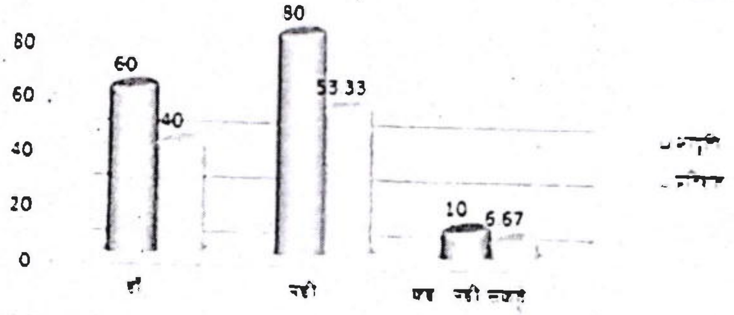

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अध्ययनगत उत्तरदाताओं में से 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि जिला प्रशासन को प्रदेश के विरोधी दल के जन प्रतिनिधियों द्वारा आरोपित किया जाता है। है। वहीं 53.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि जिला प्रशासन को प्रदेश के विरोध दल के जन प्रतिनिधियों द्वारा आरोपित किया जाता है। है। जबकि 6.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तटस्थता बनाते हुए अपना मत व्यक्त नहीं किया।

निष्कर्ष

21वीं सदी में भी भारत एक ग्राम प्रधान देश है, जहाँ आज भी 5,75,000 गाँव है, जिनमें देश कुल जनसंख्या का 72.22 प्रतिशत निवास करता है। इन गाँवों में मुख्यतः जीविका का प्रमुख साधन कृषि है। गाँवों का उत्पादन ही भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। गाँवों से हमें सब प्रकार के अनाज, दाल, फल व सब्जियाँ, दूध इत्यादि मिलते है। इतना ही नहीं भारत के बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग-व्यवसाय, जैसे कपड़ा, चीनी, वनस्पति, तेल, चाय जूट आदि अपने कच्चे माल के लिए ग्रामीणों पर ही निर्भर है। भारत की सम्पूर्ण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में गाँवों का अत्याधिक महत्व है।

Seth R.C.S. Arts & Commerce (...) DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College Durg (C.G.)

14

सुझाव

[illegible] ग्रामीण विकास आयोजन की सफलता हेतु [illegible] अत्यन्त आवश्यकता है। [illegible]

(2) ग्रामीण विकास योजनाओं में स्थानीय जनता का सहयोग- [illegible] अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और [illegible]

(3) ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए- ग्रामीण औद्योगीकरण [illegible] सबसे बड़ी आवश्यकता है। [illegible] और विकास में ही निहित है [illegible]

(4) आयोजन में [illegible] और [illegible] की प्राथमिकता दी जाए- ग्रामीण विकास आयोजन में [illegible]

(5) [illegible] ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व [illegible] प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]

Seth R.C.S. Arts & Commerce College
DURG
Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)